राज्यन्सभा

तारांकित प्रश्ना संख्यार*128

09 मार्च, 2016 को उत्त*र के लिए

भारतीय इस्पात उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने की नीति

128* **श्री परिमल नथवानी:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन-सा स्थान है और भारत में कच्चे इस्पात के उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है तथा आगामी तीन वर्षों में इसकी अनुमानित क्षमता कितनी-कितनी होगी;

(ख) क्या वर्ष 2014-15 के पश्चात देश में न्यूनतम दक्षता स्तर (एम ई एस) के आकार वाली नई कंपनियां/संयंत्र स्थापित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने के लिए कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश को विश्व का इस्पात केन्द्र बनाने की सरकार की मार्गदर्शी-योजना में झारखंड राज्य को भी शामिल किया गया है?

उत्तङर

इस्पा2तऔर खान मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

“भारतीय इस्पात उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने की नीति” के बारे में श्री परिमल नथवानी, संसद सदस्य द्वारा राज्यासभा में दिनांक 09 मार्च, 2016 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *128 के भाग (क) से (ङ) **के संबंध में विवरण**

(क): और (ख) विश्वू इस्पा त संघ (डब्ल्यू.एस.ए.) द्वारा जारी अंनतिम रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2015 में भारत विश्वि में क्रूड इस्पा त का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जेपीसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में भारत की क्रूड इस्पा ात की उत्पादन क्षमता 109.85 मिलियन टन है और अप्रैल-दिसम्बएर, 2015-16 में 116.74 मिलियन टन (अंनतिम) है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान देश में इस्पाबत की उत्पा.दन क्षमता में 6.5 प्रतिशत कम्पांउन्ड1 एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) की वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2015-16 में भी इस प्रवृति के जारी रहने और तत्पश्चा5त् इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) और (घ): एक उदारीकृत और नियंत्रण मुक्ते अर्थव्यावस्थाद में सरकार की भूमिका एक सुविधादाता की होती है। एक सुविधादाता के रूप में सरकार घरेलू उद्योग में विकास को प्रोत्सातहित करने और विश्वू स्त र पर इसे प्रतिस्प र्धात्म्क बनाने के लिए उपयुक्ती वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करती है तथा संस्थासनिक तंत्र और ढ़ाचा का निर्माण करती है। राष्ट्री□य इस्पानत नीति2005 में आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर वृद्धि को प्रोत्सा हित करने के लिए विस्तृतत रोड़ मैप तैयार किया गया है। राष्ट्री□य इस्पांत नीति 2005 का दीर्घ कालीन लक्ष्यत यह है कि भारत के पास विविध प्रकार के इस्पाटत की मांग को पूरा करने के लिए विश्वक स्तृर का आधुनिक और कुशल इस्पाित उद्योग होना चाहिए। इसलिए मुख्यष जोर विश्वि स्त्र पर प्रतिस्प र्धात्मककता प्राप्तउ करने के लिए है। इस्पाुत एक नियंत्रण मुक्त् क्षेत्र है जिसमें निवेश संबंधी निर्णय और निधियों का आवंटन निवेशकों द्वारा वाणिज्यिक और बाजार सोच-विचारों के आधार पर किये जाते है तथा इस उद्देश्यर के लिए सरकारी निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है।

(ङ): जी , हॉ। झारखण्डस इस्पाित का उत्पारदन करने वाला एक प्रमुख राज्य है और वह भविष्य में भी इस क्षेत्र में ठोस प्रगति जारी रखेगा। सेल का झारखण्ड में बोकारो इस्पा त संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा गुआ और चिरिया खानों आदि के विस्ता्र पर 19,000 करोड़ रूपये से भी अधिक निवेश करने का प्रस्ता व है। इसके अतिरिक्तस, झारखण्डा में एक स्पे शल पर्पज व्ही्कल (एसपीवी) के जरिए 18000 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता (एमटीपीए) का एक ग्रीनफील्डअ इस्पा त संयंत्र की स्था्पना करने के लिए भारत सरकार, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी), (इस्पापत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम) और झारखण्डर सरकार ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताकक्षर किए हैं।

***